

राजकीय विद्यालय में उत्कृष्ट अटल टिंकरिंग व आईसीटी लैब हुआ स्थापित, उद्घाटन में शमिल हुए जिलाधिकारी शिक्षाधिकारी

महेन्द्र शंख मीना

राजस्थान: बजावा सुपों का विद्यालय में उत्कृष्ट अटल टिंकरिंग व आईसीटी लैब जिला शिक्षा अधिकारी व एपीसी ने किया अवलोकन। जिला के राजकीय विद्यालयों में भी अब स्तरीय लैब स्थापित हो व उनका सुनियोग हो रहा है।

शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी मनोज ढाका व आईसीटी एपीसी कमेश तेतरवाल ने राजस्थान में काम करने वाली विद्यालयों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य महिमाल, लैब प्रभारी अध्यापक तंवर अजय श्रीमान व विकास अवान ने विद्यालय में दिखाया कि राजकीय विद्यालय में ऐसी लैब होना गर्व कात है।

लैब में विद्यार्थी मॉडल्स बना रहे थे, श्री डी प्रिंटर के माध्यम से सहयोग से स्थापित अटल टिंकरिंग लैब व भाषाशाहों के सहयोग से स्थापित आईसीटी लैब का



अवलोकन करवाया। लैब इतनी शादार, सुरक्षित व कियाशाल पाई गई कि राजकीय विद्यालय में ऐसी लैब होना गर्व कात है।

लैब में विद्यार्थी मॉडल्स बना रहे थे, श्री डी प्रिंटर के माध्यम से बनने वाले मॉडल व अन्य वस्तुएं

देखते ही बनती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज में काम हो रहा है। जिन प्रतिदिन विद्यार्थी अध्यापक क्रय हैं।

डीईओ ढाका ने एपीसी को निर्देश दिए कि ऐसे विद्यालय में अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरणीय है। लैब में जनसहयोग से 20 कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, आई-एफॉनी लगे हुए हैं। जिन प्रतिदिन विद्यार्थी अध्यापक क्रय हैं।

डीईओ ढाका ने एपीसी को निर्देश दिए कि ऐसे विद्यालय में अन्य विद्यालयों के अध्यापकों व

विद्यार्थियों को विजिट करवानी चाहिए।

इसी विद्यालय में कार्यरत पति पनी विकास आवं व्याख्याता इतिहास व सुनीता कुमारी व्याख्याता भूगोल से भी अधिकारियों ने आगामी प्रिंटर व लैब एपीसी पर चाचों की। उल्लेखनीय है कि इसी दमपति ने मिशन हैंडेंड के तहत इतिहास व भूगोल के प्रश्न बैक बनाये हैं जो पूरे राजस्थान में विभाग द्वारा प्रसारित किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य व स्टाफ के प्रयोगों को सराहना करते हुए नामांकन वृद्धि, व्यवसायिक शिक्षा पर भी प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राजकाला व्याख्याता रेखा अकादमी (वॉचवा/हडप्सर) के अशुभ रविवार क्षेत्रसागर पर प्रशासनिक परिसर के लिए हूआ था। अबेक्स गणनाओं की शीघ्र एवं सटीकता सुभम कांबले ने तीसारा पुरस्कार

पुणे के कोल्हापुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रोएक्टिव अबेक्स प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों को मिली सफलता



रियाज अब्दुल गफ्फर शेख

महाराष्ट्र: पुणे के कोल्हापुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रोएक्टिव अबेक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा विराग भाटी ने अबेक्स के अठ स्तर पूरे किए और उन्हें "प्रोएक्टिव अबेक्स" की उपाधि मिली।

और अरशद मोमिन और मयूर अबेक्स बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करता है। एकाग्रता और यादाशंक बढ़ाता है। ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा विराग भाटी ने अबेक्स के अठ स्तर पूरे किए और उन्हें "प्रोएक्टिव अबेक्स" की उपाधि मिली। प्रतियोगिता में 100 गणित हल करने के लिए छह मिनट का समय दिया गया। प्रतियोगिता में लक्ष्य श्रेणी अधिकारी ने प्रधानाचार्य व स्टाफ के प्रयोगों को सराहना करते हुए नामांकन वृद्धि, व्यवसायिक शिक्षा पर भी प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राजकाला व्याख्याता रेखा अकादमी (वॉचवा/हडप्सर) के अशुभ रविवार क्षेत्रसागर पर प्रशासनिक परिसर के लिए हूआ था। अबेक्स गणनाओं की शीघ्र एवं सटीकता सुभम कांबले ने तीसारा पुरस्कार

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई तहसीलदारों का हुआ तबादला

शेख कलीम शेख

महाराष्ट्र: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तहसीलदारों के तबादले बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी शामिल बुलडाणा, 2 फरवरी लोकसभा आयोजन 2024 के तहसीलदार सभागंगे कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा प्राप्त सरकारी आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आदेश के अनुसार, बुलडाणा के तहसीलदार रुपेश खड़गे भी योग्य तबादले के तहसीलदार आदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कुल 21 अधिकारी शमिल हैं और बुलडाणा जिले के पांच तहसीलदारों का बुलडाणा किले से है।

उप सचिव अंजलि देशमुख द्वारा जिले के तहसीलदार आद

संपादकीय

‘विकसित भारत’ दूर की कौड़ी

अंतरिम बजट को 'विकसित भारत' की संभावनाओं का दस्तावेज मान कर विश्लेषण किए गए हैं। वर्ष 2047 अभी बहुत दूर है। अभी भारत की कुल अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। विकसित राष्ट्र के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था का बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश के लोगों की जीवन-शैली, जीवन-स्तर, आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और तकनीकी सुविधाएं और सुधार और व्यापक रोजगार आदि भी बेहतर दर्जे के होने चाहिए। फिलहाल शिक्षा पर औसतन 3.8 फीसदी और स्वास्थ्य पर मात्र 1.3 फीसदी ही खर्च किया जाता है। अर्थशास्त्री लंबे अंतराल से दलीलें देते रहे हैं कि जीडीपी का कमोबेश 6-6 फीसदी हिस्सा इन क्षेत्रों पर खर्च किया जाना चाहिए। इनके अलावा, कृषि की औसत विकास-दर मात्र 1.8 फीसदी रह गई है, जबकि कारोना महामारी के दौर में भी यह 3 फीसदी से अधिक थी। हमारी जीडीपी में कृषि की 18-20 फीसदी भागीदारी है, लेकिन अभी एक वैश्विक रपट सामने आई है, जिसका एक निष्कर्ष यह भी है कि दुनिया की 54 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसमें किसानों की खेती वर्ष 2000 से लगातार घाटे मैं हैं। अंतरिम बजट में भी 1.27 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक की राशि कृषि मंत्रालय को आवंटित करने की घोषणा की गई है।

यह एक छिपा-दबा तथ्य है कि फसल बीमा का बजट 2.7 फीसदी, अनन्दाता संरक्षण का बजट 21 फीसदी, यूरिया सबसिडी का बजट 7.5 फीसदी घटा दिया गया है। किसान और खेती तो प्रधानमंत्री मोदी के फोकस वाले चार बग्गों में से एक हैं। विशेषज्ञ 'मौजूदा दौर को 'कृषि का संकट काल' मानते हैं। वित्त मंत्री बजट कम करने का कारण बता देतीं, तो हम विचार कर सकते थे। बहरहाल भारत का जो जीडीपी है और विकास-दर 7 फीसदी के आसपास रही है, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था 2030 तक दोगुनी नहीं हो सकती। अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण हैं कि विकास-दर कमोबेश 11-12 फीसदी लगातार रहनी चाहिए। यदि गति ऐसी नहीं रहती है, तो 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने में 10 साल लग सकते हैं। फिर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के समीकरण खटाई में पड़ सकते हैं। 'विकसित भारत' का सपना मीठा और सुखद लगता है, इस पर राजनीतिक प्रचार भी खुब किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आधार वर्ष 2024 तक ऐसे हैं, जिनके मद्देनजर 'विकसित देश' का व्यार्थ फिलहाल दूर की कौड़ी लगता है। दरअसल हमारा बजट घटे का है। यह स्थिति जुलाई के पूर्ण और आम बजट में भी रहेगी।

अंतरिम बजट में
किसानों को कोई
राहत नहीं दी गई
गरीबों को भी कुछ
नहीं दिया गया
युवाओं को भी कुछ
नहीं मिला महिलाओं
के हाथ में भी कुछ
नहीं आया महंगाई
और बेरोजगारी से
आम आदमी त्रस्त है
बजट में उसके लिए
भी कुछ नहीं है
इसके बाद भी
सरकार 2024 का
लोकसभा चुनाव
400 से ज्यादा
सीटों पर जीतने का
लक्ष्य लेकर चल रही
है इससे सभी को
हैरानी हो रही है।

5

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में तैयार हुआ अंतरिम बजट

-सनत जैन-



रुपए का भुगतान कर्ज की अदायगी के रूप में करना पड़ा। अप्रैल 2024 के बाद के वित्तीय वर्ष में सरकार को 11 लाख 90000 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में चुकाना होगे। जो वर्तमान बजट का लगभग 40 फीसदी होगा। भारत के ऊपर जो डोमेस्टिक कर्ज है भारत सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसका 40 फीसदी अकेले कर्ज और ब्याज की भुगतान में जा रहा है जिसके कारण राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है राजकोषीय घाटे से कम भारत में बचत वित्तीय संस्थानों में जमा हो रही है राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए डोमेस्टिक क्रैश मिल पाना मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार को मजबूरी बस अब विदेशी बांड की तरफ जाना पड़ रहा है।

र अंतरिम बजट लाना पड़े। कों ने अपना खुद का पूँजी भारत में जो बड़ी-बड़ी पहली ही है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट रा हो रहा है वित्तीय संरक्षण ल इन्वेस्टमेंट किया गया है। वित्तीयों द्वारा जो निवेश किया ही हुआ जिसके कारण स्थिति होती चली जा रही है भारत की बचत भी पहले की तुलना में विजर्व बैंक भी भारत सरकार देने की स्थिति में नहीं है र पूरा करने के लिए भी अब से सरकार को कर्ज मिलना मुश्किल है। केंद्र सरकार का आवाहन अगुलन लगातार बिगड़ा जा जाया है, नियांत कम हो जाया है, 5 वर्षों से सरकार कर्ज ले ही है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़ी गिरावट की ओर है संगठित के दौर से गुरु रहा है गैर संस्कार रत का लड़खड़ा रहा है इसमें एफ ने बड़ी चिंता जाता है इसके दौर सरकार की कर्ज की लिमिट



हो चुकी है विदेशी कर्ज लेने के बाद भारत सरकार को टैक्स भी बढ़ाने होंगे और सब्सिडी घटाना होगी सरकार को अपने खर्च भी घटाने होंगे सरकार को कर्ज भी घटाना होगा सरकार ने बजट में प्रवाधन कर लिए थे लेकिन सरकार के पास राशि खर्च करने के लिए उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण सैकड़े परियोजनाएं जिन में कैपिटल इन्वेस्मेंट है वह पैसे के अभाव में 5 साल तक लेट चल रही है। एक्सप्रेसवे और रेलवे में भारत सरकार द्वारा बड़ा पूँजी निवेश किया गया है लेकिन इसका रिटर्न भी सरकार को नहीं मिल पा रहा है भारतीय निवेशक इसमें निवेश भी नहीं कर रहे हैं जिसके कारण स्थिति और भी खराब हो रही है भारतीय उद्योगपतियों ने जहां परियोजनाएं चल रही हैं वहां के आसपास की जमीनों और व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से कमाई की जा रही है इससे जमीनें महंगी हुई हैं आम आदमी पर खर्च बढ़ा है लेकिन इसकी बेहतर स्थिति अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिली जो मिलनी चहिए थी आईएफएम ने भारत सरकार को वित्तीय संतुलन बनाने के लिए कर्ज कम करने सरकार की खर्च घटाने के लिए टैक्स बढ़ाने तथा सरकार की खर्च घटाने के लिए ठोस निर्णय लेने पर ही विदेशी सहायता मिलने की बात कही है सरकार अब बुरी तरीके से दबाव में है। अंतरिम बजट में अभी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है केंद्र सरकार ने 26 योजनाओं में जरूर कटौती की है लेकिन जुलाई माह में जो आम बजट आएगा उसमें निश्चित रूप से सरकार को सभी किस्म के टैक्स बढ़ाने होंगे सब्सिडी को कम या खत्म करना होगा लोक लुभावन योजनाओं को भी बंद करना पड़ेगा। जिसके कारण भारत सरकार को अनें वाले वर्षों में काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। 2024 के आम चुनाव में जो भी सरकार बनेगी उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने और कर्ज घटाने का भारी दबाव होगा।

कैंसर नियंत्रण की दिशा में उठाने होंगे बड़े कदम

-रमेश सराफ धमोरा-

कैंसर एक ऐसी रसनत ही घबराहट हो जाता है जिसका व्यक्ति बीमारी के नाम से डर जाता है वह गुजरता ही है उसके परिवार को भी बहुत गुजरना पड़ता है। उसी ही कैंसर की बीमारी की अधिक शारीरिक पर्याप्ति है। कैंसर की बीमारी जिसमें मरीज की मौत होती है। बीमारी की पीढ़ी मैरिज घुट-घुट कर

कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस का जन्म 4 फरवरी 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी के कारण होने वाले

सम्पूर्ण जीणोंद्वार की राह पर कांग्रेस

-तनवीर जाफरी-

स्वतंत्रता संग्राम
निभाने वाली कांग्रेस
साथ कई मोर्चों पर
विपक्ष के प्रति 'दुश्मन'
कांग्रेस व कांग्रेस ने
बना हुआ है वहीं का
पल रह 'आत्मन के
है। अनेक अवसरवा
किसी न किसी बहा
छोड़कर बल्कि क
विचारधारा को भी
भारत के निर्माण में
बजाय साम्प्रदायिकत
लगे हैं। अनेक ऐष
छोड़कर भयवश स
बैठे हैं और किसी ज
करने के बजाये सुरि
कर रहे हैं। इतना ही
द्वाईडियाह गठबंधन
दल भी सीट शेयरिंग
कमतर आंकने की
गोया ऐसे बक्त्र में
गठबंधन को एकजु
सन्देश देना चाहिये ऐ

1933 में संघ ने पहली बार जागरूकता इस रोग के दुनिया भर मिथ्याने तथा ऐसे बचाने 14 में इसे 5 पर केंद्रित रखकर को कम संवर्धित है। 5 करोड़ से गारी से दम लोग समय वर्ग) मर जाते हैं कि इस बढ़ाने के व्यावहारिक रूपों में एक करोड़ यदि विश्व के केंद्र कारण समय से पहले होने वाली मौतों में 25 प्रतिशत कमी के लक्ष्य को हासिल किया जाए तो हर साल 15 लाख जीवन बचाए जा सकते हैं। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में है। 2020 में 1.93 करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आए हैं। जिनमें 14 लाख से अधिक भारतीय हैं। इन्हाँ नहीं भारत में सालाना बढ़ते कैंसर मामलों के चलते 2040 तक इनकी संख्या में 57.5 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी होने की आशंका है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार देश में कैंसर के मामलों की संख्या 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का अनुमान है। जिसके लिए सरकार को चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। तभी समय पर कैंसर मरीजों की जांच से पहचान कर सही उपचार कर देकर उनकी जान बचाई जा सकती है।

नई दिल्ली रिथर्न भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा है कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में कैंसर की सही निगरानी नहीं हो पा रही है।

जिस कारण अधिकांश मामलों में बीमारी का देरी से पता चल रहा है। देश के सभी शोध केंद्रों को पत्र लिख आईसीएमआर ने कैंसर की जांच और निगरानी को आसान बनाने के लिए प्रस्ताव मार्गे हैं। देश के सभी जिलों में कैंसर निगरानी और जांच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान के तहत नई नीति बनाने के लिए आईसीएमआर को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए अलग-अलग शोध टीमें गठित होंगी और भौगोलिक व स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति के आधार पर वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित किए जाएंगे।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर से साल 2020 में 7,70,230, 2021 में 7,89,202 और 2022 में 8,08,558 लोगों की मौत हुई है। देश में कैंसर के मामलों की कुल संख्या 2022 में 14,61,427 रही। वहाँ 2021 में यह 14,26,447, जबकि 2020 में 13,92,179 थी। सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ 2020 में 2,01,319, 2021 में 2,06,088 और 2022 में 2,10,958 मरीज मिले। वहाँ

में कम कैंसर मरीज केंद्र शासित प्रदेश द्वाप्र में हैं। यहां 2020 में 27, 2021 2022 में 28-28 मरीज मिले हैं। कैंसर रोगों का एक समूह है जो मान्य कोशिकाओं की अनियन्त्रित वृद्धि प्रसार से होता है। ये कोशिकाएं ट्यूमर क द्रव्यमान का निर्माण कर सकती हैं। गरीर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप सकती हैं। जबकि कैंसर किसी को भी वेत कर सकता है। यह पहचानना श्यक है कि कुछ जीवनशैली विकल्प, धूमपान, खराब आहार और शारीरिक विधि की कमी, कैंसर के विकास के ब्रम को बढ़ा सकते हैं।

इल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉडों का कैंसर (लंग्स कैंसर) सबसे ज्ञानकैंसर हो सकता है। हमारे देश में लंग्स कैंसर के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का अनुमान है कि 2023 के द्वारा तक करीब 2.38 लाख से ज्यादा में लंग्स कैंसर मिल सकता है।

वेश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम है 'गैप को बंद करें।' यह कैंसर देखभाल विशेषक असमानताओं को रेखांकित करती है।

विपक्षी दलों की साथ दाव पर

-योगेंद्र योगी

गत वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में जीत हासिल करने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि केंद्र की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को बख्खेगी नहीं। झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में हुई गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गई। आश्वय यह है कि विपक्षी दल सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा पर राजनीतिक विद्वेषता से कार्रवाई करने का आरोप तो लगा रहे हैं, किन्तु यह एक बार भी नहीं बताया कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उनके पास क्या रोडमैप है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है, उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके विपरीत केंद्र की भाजपा सरकार को समझ में आ गया है कि देश के मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम के समर्थन में हैं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की काफी कोशिश की, किन्तु कामयाबी नहीं मिल सकी। फ्रांस से खरीदे युद्धक विमान राफेल, अडानी और अंबानी को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें साराहीन मान कर खारिज कर दिया। इससे भाजपा का नैतिक बल बढ़ गया। भाजपा ने भ्रष्टाचार की मुहिम को तेज करने के साथ ही सोरेन जैसे नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की। विपक्ष भ्रष्टाचार पर बदले की नीतय का आरोप लगा रहा है, किन्तु प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के ज्यादातर मामलों में अदालतों से जमानत तक नहीं मिल सकी। इससे जाहिर होता है कि ईडी और सीबीआई ने ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। तृणमूल कांग्रेस और आप सहित कई पार्टियों के नेता जमानत नहीं मिलने के कारण महीनों-सालों से जेलों में बंद हैं अदालतों ने यह माना है कि इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार में जो तो हो रहा है, वह जितें।

लिप्त हाने के पर्यांत सबूत मिले हैं। यही वजह है कि इनको जमानत नहीं मिल सकी, ताकि सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सके। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित 14 दलों ने ईडी और सीबीआई पर दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। विपक्षी दलों का तर्क था कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ईडी की ओर से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95 प्रतिशत विपक्षी दलों से हैं। सीबीआई की ओर से 124 जांचों में से 95 प्रतिशत से अधिक विपक्षी दलों से हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष मामले के तथ्यों के बिना सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है। सीजेआई ने कहा कि जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो तो हमारे पास वापस आएं। मामले के तथ्यों से संबंध रखे बिना सामान्य दिशा-निर्देश देना खतरनाक होगा। इस पर विपक्षी दलों ने याचिका वापस ले ली। ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं को जमानत नहीं मिलने और सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को मिली हार के बाद भाजपा के हासले बुलंद हो गए। यही वजह है कि विगत विधानसभा चुनाव और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता प्रश्नाचार के खिलाफ हुंकार भरते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास ही बज रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले का सामना कर रहे हैं। इस मामले में ईडी ने केजरीवाल को चार समन भेजे हैं, लेकिन वो अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर करीब एक दर्जन से अधिक विपक्षी नेता हैं। देर-सवेर इनका भी बच पाना मुश्किल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोप है कि रेवंत जब टीडीपी में थे, तो उन्होंने साल 2015 में विधान परिषद के चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक विधायक को कथित तौर पर पचास लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और वार्ड-एसआर कांग्रेस के मुख्या जगन मोहन रेडी पर भी प्रवर्तन निदेशालय की नजर है।

NCR
સમાચાર

संपादकीय कार्यालय
जी-12/276, संगम विहार, नई
दिल्ली-110062. सोमवार से शनिवार
प्रातः 9:00 से सायं 9:00
फोन: 8888883968, 9811111715

एनसीआर समाचार के समस्त पाठकों तथा पत्र के साथ जुड़े समस्त पत्रकारों, व्यावसायिक संयोजक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि गत वर्षों से श्री बलबीर सिंह के नेतृत्व व स्वामित्व में चले आ रहे वर्तमान एनसीआर समाचार पत्र का प्रकाशन व स्वामित्व मो. हनीफ, पुत्र श्री इस्माईल खान मास्टरजी, संगम विहार के स्वामित्व व नेतृत्व में हो रहा है। अतः भविष्य में समस्त प्रकार की व्यावसायिक, कानूनी एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु मो. हनीफ/ नये कार्यालय जी 12/276, संगम विहार, नई दिल्ली - 110062, दूरभाष (मोबाईल) 8888883968, 9811111715 से सम्पर्क करें।

